

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 08/2026

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण: -

1. AUTHAM INVESTMENT &
INFRASTRUCTURE LTD
पता:-THE RUBY, 11TH
FLOOR, NORTH-WEST
WING, PLOT NO. 29,
SENAPATI BOPAL MARG,
DOBAR(WEST) MUMBAI-
400028

क्षेत्रीय कार्यालय:- DREAM
HEIGHTS PLOT NO. 5-6
MARWARI CATALYSTS,
CYB95, CYBER PARK
HEAVY INDUSTRIAL
AREA, JODHPUR 342005
राजस्थान जरिये प्राधिकृत
अधिकारी अमरजीत सिंह
पंवार।

1. MR. DHIRAJ PURI
2. MRS LILA DEVI
ADD:- COURT KE PASS
BALOTRA.
ALSO ADD WARD NO 35
SAMUDAYIK BHAWAN KE PASS
BALOTRA.
ALSO ADD PLOT NO 19 ZONE D
MARK KHA INDRA GANDHI
NAGAR SECOND EXT. VILLAGE
BALOTRA.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1. श्री दुर्गेश दैय्या अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

दिनांक:- 06.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण धीरज कुमार व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।
2. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण कोड संख्या RHAHJOD000063890 के तहत राशि 11,50,000/-रु, ऋण कोड संख्या RHAHJOD000066092 के तहत राशि 4,50,000/-रु कुल राशि रूपये 16,00,000/- (अक्षरे सोलह लाख रूपये) मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण श्रीमती लीलादेवी की मारगेज आवासीय सम्पत्ति, जो भूमि, भवन एवं ढांचा सम्पूर्ण सम्पत्ति प्लॉट नंबर 19 जॉन डी मार्क ख इन्दरा गांधी नगर बालोतरा, जिला बालोतरा, जिसका कुल क्षेत्रफल 612.6 वर्ग फीट है, जिसकी



चतुर्थ सामाएं उतर में धीरजपुरी का प्लॉट, दक्षिण में नाथुराम का प्लॉट, पूर्व में रनजीतसिंह का प्लॉट एवं पश्चिम में 30 फीट रोड़ आया हुआ है, को प्रार्थी बैंक /कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 09.10.2021 तक कुल राशि 18,23,5307/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक की रिट याचिका संख्या 9694/2005 सुनन्दा कुमारी वगैरह बनाम स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उप धारा के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2022 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है:- **14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset**

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured assets, request, in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan



Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him—

(a) take possession of such asset and documents relating thereto; and


(b) forward such asset and documents to the secured creditor:

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

4. अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी के पक्ष में बंधक आवासीय अचल सम्पति आवासीय रिहायशी अप्रार्थीगण श्रीमती लीलादेवी की मारगेज आवासीय सम्पति, जो भूमि, भवन एवं ढांचा सम्पूर्ण सम्पति प्लॉट नंबर 19 जॉन डी मार्क ख इन्दरा गांधी नगर बालोतरा, जिला बालोतरा, जिसका कुल क्षेत्रफल 612.6 वर्ग फीट है, जिसकी चतुर्थ सामाएं उत्तर में धीरजपुरी का प्लॉट, दक्षिण में नाथुराम का प्लॉट, पूर्व में रनजीतसिंह का प्लॉट एवं पश्चिम में 30 फीट रोड़ आया हुआ है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बन्धक रखा था। जिसका भौतिक कब्जा व उससे संबंधित अन्य दस्तावेज जो अप्रार्थी के कब्जे में हों को प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को उक्तानुसार पालनार्थ, संबंधित पुलिस थाना को निर्देशित करने हेतु प्रेषित हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस बी सिविल रीट पीटिशन नंबर 14419/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही जारी हो।

5. आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सुशील कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा